हमने प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने सीआईआई (राजस्थान) के वार्षिक सत्र में कहा कि राजस्थान में उद्यमियों को परेशानी नहीं आने दी जायेगी

जयपुर, 12 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने निवेशपरक वातावरण, नवाचारों को प्रोत्साहन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित विभिन्न ऐसे निर्णय किए हैं, जिससे प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हुआ है। हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजस्थान में निवेश करने वाले उद्यिमयों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी तथा उनकी सभी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री गुरुवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) राजस्थान के वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं, नवाचारों एवं कार्यक्रमों द्वारा प्रदेश में विकास को गति दी है। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ ही सड़क नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध है। राज्य सरकार इनकी प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। इस दौरान शर्मा ने युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के नियुक्ति पत्र तथा महिलाओं को उद्यिमता के लिए वाउचर पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर सीआईआई (उत्तर क्षेत्र) की अध्यक्ष अंजली सिंह और सीआईआई राजस्थान के अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं उद्यमी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के नियुक्ति पत्र तथा महिलाओं को उद्यिमता के लिए वाउचर पत्र सौंपे।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एयर कनैक्टिविटी के साथ सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ किया है। राज्य सरकार खनिजों की प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान दे रही है।**

ईरान युद्ध में चार भारतीयों की मौत

नई दिल्ली, 12 मार्च। भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के चलते 4 भारतीय अपनी जान गंवा बैठे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अंतर मंत्रालयी पत्रकार वार्ता में गुरुवार को बताया कि वर्तमान में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण तीन भारतीयों की मौत हुई है और एक भारतीय लापता है। मरने वाले भारतीय हमले का शिकार बने व्यापारिक जहाजों पर कार्यरत थे। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक हमने तीन भारतीय नागरिकों को खो दिया है और चौथा भारतीय नागरिक लापता है। हाल ही में एक भारतीय की मौत मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाले जहाज सेफसी विष्णु पर हुई है। यह घटना इराक के पास घटी है। मंत्रालय उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में अब तक 24 से अधिक भारतीय नागरिकों के घायल होने की पुष्टि हुई है।

ओम बिड़ला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करना चाहता हूं कि मैं हमेशा सभी सांसदों को बोलने की अनुमति देता हूं, लेकिन नियमों और विनियमों (रुल्स एंड रेग्यूलेशंस) के तहत।"

ओम बिड़ला ने गुरुवार को कहा, "आइए, हम इस लोकसभा की कार्यवाही को नियमों के अनुसार चलाएं। ये नियम सभी के लिए समान हैं, विपक्ष और सरकार दोनों के लिए।"

अमेरिका -इज़रायल की सदाबहार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रोकना चाहता है। इराक और अफगानिस्तान में लंबे और विवादित हस्तक्षेपों ने अमेरिकी जनता और राजनीतिक नेतृत्व को अनिश्चित अवधि तक चलने वाले युद्धों से सावधान कर दिया है। यहां तक कि जब अमेरिका शुरुआत में सैन्य कार्रवाई का समर्थन करता है, तब भी आमतौर पर कांग्रेस, सहयोगी देशों और घरेलू जनमत की ओर से तनाव को सीमित रखने और कूटनीतिक समाधान तलाशने का दबाव बना रहता है।

विश्लेषकों का कहना है कि यदि युद्ध बिना किसी स्पष्ट और त्वरित समाधान के जारी रहता है, तो दोनों देशों के नज़रिए में यह अंतर वॉशिंगटन में पॉलिसी डिबेट्स को प्रभावित कर सकता है। लंबे संघर्ष के आर्थिक प्रभाव सबसे पहले तनाव का कारण बन सकते हैं। ईरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज़ स्ट्रेट के पास स्थित है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल परिवहन होता है। नए सुप्रीम लीडर्स के इशारे पर शिपिंग तथा रूट्स एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर में रूकावट से दुनियाभर में तेल की कीमतें ऊंची रहेंगी और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई का दबाव बढे गा। अमेरिका में ईंधन की कीमतें सीधे जनभावना से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं, इसलिए प्रशासन पर क्षेत्र को जल्दी स्थिर करने का राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है।

कूटनीतिक पहलू भी दोनों के बीच दूरी बढ़ा सकते हैं। वॉशिंगटन को केवल इज़रायल ही नहीं, बल्कि यूरोपीय सहयोगियों और खाड़ी देशों के साथ भी संबंध संभालने होते हैं, जिनके आर्थिक और सुरक्षा हितों पर लंबे युद्ध से असर पड़ सकता है। यूरोपीय संघ के देश और खाड़ी के बड़े ऊर्जा उत्पादक देश संघर्ष के बढ़ ने पर तनाव कम करने की मांग कर सकते हैं, खासकर तब, जब युद्ध से जहाजरानी मार्ग, व्यापार और ऊर्जा बाजार प्रभावित होने लगें। ऐसे में अमेरिका को, इज़रायल की लगातार सैन्य दबाव बनाए रखने की इच्छा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयम व बातचीत की मांग के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है।

एक और संभावित तनाव का बिंदु सैन्य लक्ष्यों को लेकर हो सकता है। इज़रायल पूरे इलाके में ईरानी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सैन्य ठिकानों और प्रॉक्सी नैटवर्क पर हमले जारी रखने के पक्ष में हो सकता है। लेकिन अगर इन कार्रवाइयों से और देशों के शामिल होने या युद्ध के भौगोलिक रूप से फैलने का खतरा बढ़ ता है, तो अमेरिका ज्यादा सावधानी बरत सकता है। ऐसे में अमेरिका को इज़रायली अभियानों का समर्थन करने के फायदों को एक बड़े रीजनल युद्ध में घसीटे जाने की संभावना के साथ तोलना होगा।

हालांकि इसका यह मतलब नहीं होगा कि अमेरिका-इज़राइल साझेदारी टूट जाएगी, क्योंकि यह गहरे रणनीतिक और राजनीतिक आधार पर टिकी है। लेकिन लंबे युद्ध अक्सर करीबी सहयोगियों के बीच भी प्राथमिकताओं के सूक्ष्म अंतर को उजागर कर देते हैं। जो अभियान शुरुआत में पूरी तरह एकजुट दिखता है, वह धीरे-धीरे सैन्य कार्रवाई की गति, दायरे और उद्देश्यों को लेकर बातचीत का रूप ले सकता है। यदि संघर्ष जारी रहता है और इसका खर्च बढ़ ता है, तो वॉशिंगटन तनाव कम करने का रास्ता तलाशने पर अधिक जोर दे सकता है, जबकि इज़रायल तब तक दबाव बनाए रखने पर केंद्रित रह सकता है, जब तक उसे यह भरोसा न हो जाए कि ईरान की क्षमताएं निर्णायक रूप से कमजोर हो चुकी हैं।

ऐसी स्थिति में गठबंधन बना रहेगा, लेकिन संघर्ष के शुरुआती चरण में जो राजनीतिक तालमेल मजबूत दिखता है, वह समय के साथ अधिक जटिल हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने हितों और सीमाओं के अनुसार अपनी नीतियों को समायोजित करेंगे।

ईरान की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गारंटी।"

ईरान के राष्ट्रपति का युद्धिवराम का प्रस्ताव ईरान की सशस्त्र सेनाओं के प्रवक्ता अबुलफजल शेकरची के बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने सरकारी आईआरआईबी टीवी चैनल पर कहा कि अगर वॉशिंगटन ने ईरानी बंदरगाहों पर हमला किया, तो खाड़ी में कोई भी बंदरगाह या आर्थिक केन्द्र ईरान की पहुंच से बाहर नहीं होगा।

सशस्त्र बलों के प्रवक्ता अबुलफजल शेकरची ने कहा। "अगर हमारे बंदरगाहों और डॉक को धमकी दी जाती है, तो क्षेत्र के सभी बंदरगाह और डॉक हमारा निशाना होंगे।"

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरानी बंदरगाहों पर हमला होता है, तो सशस्त्र बल "अब तक किए गए हमलों से कहीं ज्यादा बड़ा ऑपरेशन करेंगे।"

ईरान ने युद्ध खत्म करने के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किसी समय-सीमा का उल्लेख किए बिना, अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले कुछ दिनों से बार-बार कह रहे हैं कि युद्ध "बहुत जल्द" समाप्त हो जाएगा। ट्रंप के अनुसार, सैन्य अभियान तय समय से काफी आगे बढ़ चुका है और "ईरान में टारगैट करने के लिये अब कुछ बाकी नहीं बचा है।"

संघर्ष शुरू होने से पहले अमेरिका ने चार मुख्य लक्ष्य तय किए थे-ईरान की परमाणु क्षमता को निष्क्रिय करना, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल उद्योग को पूरी तरह नष्ट करना, ईरानी नौसेना को खत्म करना और हिज़्बुल्लाह, हूती तथा हमास जैसी आतंकी सेनाओं को हथियार, धन और मार्गदर्शन देने की ईरान की क्षमता को समाप्त करना। इनमें से अमेरिका केवल दो लक्ष्य हासिल करने का दावा कर सकता है-ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और उसकी नौसेना को नष्ट करना। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में मोजतबा खामेनेई की नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन खामेनेई देश पर मजबूत नियंत्रण बनाए हुए दिखाई देते हैं और अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाने में सफल नहीं हुआ है।

संघर्ष के पहले ही दिन अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बावजूद, अमेरिका और इज़रायल ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने में असफल रहे हैं। दोनों पक्षों में से कोई भी नरमी के संकेत नहीं दे रहा है और ईरान लगातार यह कह रहा है कि वह युद्धिवराम की मांग नहीं कर रहा है।

- **यही नहीं, ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि मोजतबा को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाना उन्हें स्वीकार्य नहीं है पर अमेरिका उन्हें हटाने के लिए कुछ नहीं कर पाया है, उल्टे मोजतबा ने देश पर मजबूती से नियंत्रण कर लिया है।**

ट्रम्प अब किसी भी तरह से खाड़ी देशों के युद्ध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि अभी कई सैन्य अभियान बाकी हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया कि सैन्य अभियान बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है और इसके अधिकांश लक्ष्य पहले ही हासिल किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में अब बहुत कम लक्ष्य बचे हैं, जिन पर हमला किया जाना बाकी है। उनके बयान ऐसे लगते हैं, मानो वे पहले से ही अमेरिका के इस मुश्किल स्थिति से निकलने की कहानी तैयार कर रहे हैं।

दूसरी ओर इज़रायल का कहना है कि अभी कई महत्वपूर्ण लक्ष्य बाकी हैं, जिन्हें हासिल करना जरूरी है। इज़रायल इस संघर्ष को लंबे समय के नजरिये से देख रहा है, जिसमें उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी ईरान भविष्य में फिर से सैन्य अभियान चलाने की स्थिति में न रहे। इस प्रकार अमेरिका और इज़रायल के दीर्घकालिक लक्ष्यों और युद्ध के अंत को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।

इज़रायल की मजबूरियां स्पष्ट हैं। ईरान लगातार भारी मिसाइल हमले और विनाशकारी सैन्य कार्रवाइयां कर रहा है। इसलिए इज़रायल इस समस्या को उसकी जड़ में जाकर खत्म करना चाहता है। यदि इस युद्ध का कोई बड़ा शिकार रहा है तो वह है डॉनल्ड ट्रंप की शेखी। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी सेना होर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवा देगी और जहाजों को सुरक्षा देते हुए पार करवाएगी। लेकिन अमेरिकी रक्षा बलों ने साफ कहा है कि वे अभी इस तरह की एस्कॉर्ट सेवा देने के लिए तैयार नहीं हैं।

यह स्पष्ट है कि व्यावसायिक जहाजों को साथ लेकर होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरना बेहद खतरनाक होगा और इससे निश्चित रूप से भारी नुकसान हो सकता है। इसी कारण अमेरिकी नौसेना ने ऐसे सुरक्षा अभियान शुरू नहीं किए हैं।

ट्रंप का एक और बड़ा दावा यह था कि शेयर बाजार उनके नेतृत्व से बेहद खुश हैं और बाजार अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से शेयर बाजारों में तेज गिरावट देखी गई है। इसके साथ ही, अमेरिकी ट्रेज़री बॉन्ड की लाभ दर बढ़ गई है, जिससे अमेरिकी सरकार के लिए कर्ज लेना और महंगा हो गया है। इसका असर अमेरिका की वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है, जो पहले से ही काफी दबाव में है। तीसरा असर यह हुआ है कि युद्ध के कारण जोखिम की धारणा बढ़ गई है, जिससे अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर मजबूत हो गई है। इससे अमेरिका के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने की उसकी योजना को और झटका लग सकता है।

कुल मिलाकर अब समय आ गया है कि ट्रंप ईरान युद्ध के इस जटिल संकट से निकलने का रास्ता तलाशें। अमेरिका अब हर हाल में इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन इज़रायल के लिए स्थिति बिल्कुल अलग है। जब तक ईरान को पूरी तरह काबू में नहीं किया जाता और उसकी सैन्य क्षमता कमजोर नहीं कर दी जाती, तब तक भविष्य में फिर से संघर्ष का खतरा बना रहेगा। इसलिए इज़रायल इस युद्ध का पूरा फायदा उठाना चाहता है, भले ही इसके लिए संघर्ष को और लंबे समय तक क्यों न चलाना पड़े।

होर्मुज़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत, ए आई एस को सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए सक्रिय रखना अनिवार्य है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600